भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2221
12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न
पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण

2221. श्री नवीन जिंदलः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) आज की तिथि तक देश में कुल कितनी मात्रा में एथनॉल का उत्पादन किया गया है;
(ख) पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वास्तव में कितनी मात्रा में इथेनॉल की आवश्यकता है;
(ग) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान एथनॉल-पेट्रोल मिश्रित ईंधन से चलने वाले वाहनों के कार्य-निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा देश भर में, विशेषकर गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में बहुआयामी जैव ईंधन उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2023-24 के दौरान पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को उत्पादित और आपूर्तित इथेनॉल की कुल मात्रा लगभग 672 करोड़ लीटर थी। वर्तमान इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2024-25 में, लगभग 261 करोड़ लीटर का उत्पादन किया गया है और ओएमसी को आपूर्ति की गई है (दिनांक 23.02.2025 तक की स्थिति के अनुसार)।

(ख): इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 में पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लगभग 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ): ई20 ईंधन वाले इंजनों के साथ सामग्री अनुकूलता अप्रैल, 2023 से प्राप्त कर ली गई है। इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार ने अप्रैल 2025 से ई20 ट्यून्ड इंजन वाले वाहनों को बाजार में उतारने का लक्ष्य तय किया है। ई20 पर चलने वाले वाहनों में गैसोलीन की तुलना में ईंधन दक्षता में मामूली कमी देखी गयी है।

(ङ): देश में इथेनॉल उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने वर्ष 2018-22 के दौरान विभिन्न इथेनॉल ब्याज सहायता योजनाओं को अधिसूचित किया है। सहकारी चीनी मिलों के लिए एक नई योजना भी दिनांक 06.03.2025 को उनके मौजूदा गन्ना आधारित संयंत्रों को मल्टी-फ़ीड आधारित इथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करने के लिए अधिसूचित की गई है।

सरकार देश में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है जैसे ओएमसी को आपूर्ति के लिए विभिन्न फीड-स्टॉक से उत्पादित इथेनॉल की लाभकारी कीमतों का निर्धारण; ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल पर माल और सेवा कर (जीएसटी) में 18% से 5% तक की कटौती; इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रमुख फीडस्टॉक के रूप में मक्का को बढ़ावा देना; ओएमसी द्वारा समर्पित इथेनॉल संयंत्रों (डीईपी) के साथ दीर्घकालिक कुल खरीद समझौते (एलटीओए) आदि।

इसके अलावा, देश में उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना "प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन - वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना 2019" वर्ष 2024 में संशोधित को अधिसूचित किया गया है।

****